भारत – गांबिया संबंध

राजनीतिक संबंध :

भारत और गांबिया के बीच द्विपक्षीय संबंध अच्छे हैं तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन एवं संयुक्त राष्ट्र में एक - दूसरे के सहयोग पर आधारित हैं। गांबिया एकमात्र अंग्रेजी भाषी देश है जो मिशन द्वारा कवर किया जाता है।

वाणिज्यिक संबंध / द्विपक्षीय व्यापार :

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	भारत का निर्यात	भारत का आयात	कुल व्यापार	वृद्धि (प्रतिशत में)
2011-2012	64.21	40.16	104.37	84.97
2012-2013	55.56	30.31	85.87	-17.72
2013-2014	85.13	29.20	114.33	33.14
2014-2015	73.53	36.08	109.61	-4.13
2015-16 (अप्रैल - सितंबर)	25.38	24.98	50.36	-

स्रोत : आयात - निर्यात डाटाबेस, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार

भारत द्वारा गांबिया को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मुख्य रूप से कॉटन यार्न, फेब्रिक एवं मेडअप, कास्मेटिक / ट्वालेटरी, औषधियां एवं भेषज पदार्थ तथा सेमी फिनिस्ड लोहा एवं स्टील उत्पाद शामिल हैं, जबकि गांबिया द्वारा भारत को निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में कच्चा काजू एवं कपास शामिल हैं।

आईटीईसी तथा अन्य प्रशिक्षण एवं सहायता कार्यक्रम :

वित्त वर्ष 2015-16 के लिए आई टी ई सी के तहत गांबिया को 35 स्लॉट आवंटित किए गए हैं, जबकि आई सी सी आर के तहत छात्रवृत्तियों के 30 स्लॉट प्रदान किए गए हैं। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल) द्वारा कार्यान्वित अखिल अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना गांबिया में क्रियाशील है।

अनुदान / ऋण :

भारत ने एक ट्रैक्टर असेंबली प्लांट परियोजना के लिए लगभग 6.7 मिलियन अमरीकी डालर और राष्ट्रीय असेंबली भवन परिसर के निर्माण के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालर की दो रियायती ऋण सहायता प्रदान की है। राष्ट्रीय असेंबली के निर्माण को पूरा करने के लिए ऋण के रूप में 16.88 मिलियन अमरीकी डालर की राशि अनुमोदित की गई है। अभी हाल ही में, जुलाई, 2014 में भारत ने ग्रेटर बांजुल एरिया में बिजली परियोजना के विस्तार के लिए और ग्रेटर बांजुल एरिया में यू पी वी सी पाइपों द्वारा एजबेस्टस वाटर पाइप को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रत्येक के लिए 22.5 मिलियन अमरीकी डालर की दो ऋण सहायता को मंजूरी प्रदान की है। अप्रैल 2015 में भारत ने गांबिया में बांजुल बंदरगाह के विस्तार के लिए 92 मिलियन अमरीकी डालर और गांबिया ग्रा मीण विद्युतीकरण विस्तार परियोजना के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता प्रदान की है।

भारत की ड्यूटी फ्री टैरिफ तरजीह (डी एफ टी पी) स्कीम गांबिया से चयनित वस्तुओं के आयात के लिए लागू है। गांबिया के दो गांवों अर्थात कांकुरंग और काफेनकेंग में एक भारतीय गैर सरकारी संगठन द्वारा एक सौर विद्युतीकरण परियोजना लगाई गई जिसका उद्घाटन गांबिया के उप राष्ट्रपति डा. एजा इसातोउ नजी सैदी द्वारा सितंबर, 2007 में किया गया। अगस्त, 2010 में, गांबिया गणराज्य सरकार के तत्कालीन विदेश मंत्री महामहिम डा. ममाडोउ तंगारा की यात्रा के दौरान भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों में उपकरण प्रदान करने के लिए गांबिया गणराज्य को पांच सौ हजार अमरीकी डालर का अनुदान प्रदान करने की घोषणा की। इस संबंध में उपकरण की आपूर्ति करने की आवश्यक प्रक्रिया चल रही है। भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन एस आई सी) की सहायता से एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना है। स्थापित हो जाने पर यह केंद्र नलसाजी, वेल्डिंग, विद्युत, निर्माण क्षेत्र, बढ़ईगिरी, दस्तकारी, सर्वेक्षण, प्लास्टिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन सह-प्रशिक्षण, आई सी टी, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, जेम-स्टोन कटिंग एवं पालिशिंग आदि जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

आई ए एफ एस III एवं चौथी भारत - अफ्रीका व्यापार मंत्री बैठक :

प्रधानमंत्री के विशेष दूत (एस ई पी एम) और संसदीय राज्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भारत - अफ्रीका मंच शिखर बैठक III (आई ए एफ एस III) में भाग लेने के लिए गांबिया के शिष्टमंडल को निजी तौर पर आमंत्रित करने के लिए गांबिया का दौरा किया। गांबिया की उप राष्ट्रपति सुश्री इसातो नजी सैदी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 26 से 29 अक्टूबर 2015 के दौरान आई ए एफ एस III में भाग लिया।

गांबिया के व्यापार एवं उद्योग मंत्री श्री अडौली जोब के नेतृत्व में एक 3 शिष्टमंडल ने 23 अक्टूबर 2015 को चौथी भारत - अफ्रीका व्यापार मंत्री बैठक में भाग लिया।

एन आर आई की आबादी :

गांबिया में भारतीय नागरिकों की अनुमानित संख्या 600 के आसपास है। ये मुख्य रूप से व्यापार एवं निजी कारोबार करते हैं जिसमें निर्माण क्षेत्र भी शामिल है तथा गांबिया की फुटकर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जनवरी, 2016